JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

कोविड–19, में महात्मा गाँधी के आत्मनिर्भरता सम्बन्धी सिद्धान्तों का महत्व

डॉ0 त्रिसुख सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान
राजकीय मॉड़ल महाविद्वालय, कपूरी
गोविन्दपुर, सहारनपुर

सार– इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड–19) ने हम सभी के सामने जो एक बड़ी चुनौती खड़ी की वह यह थी की हमारे दैनिक जीवन में उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की लोकड़ाऊन के कारण उत्पादन एवं पूर्ति के बाधित होने से रोजगार लगभग समाप्त से हो गए। जिसका दंश देश के उन सभी कर्मचारियों एवं मजदूरों स्पस्ट रूप से देखने को मिला जो रोजगार के लिए अपने परिवार आदि को लेकर अपनी आजीवका चलाने के लिए शहरों में अपना जीवन यापन कर रहें थे। लकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से उन्हें पैदल व भूखें–प्यासे रहतें हुए शहरों से अपने गाँव आदि लोटना पडा। जिस कारण उनके साथ होने वाली ह्रदय विदारक घटनाऐं दिल को झकझौर देती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत विभाजन के बाद अपनी जान बचाने के लिए जिसे जो रास्ता मिला उसने वही रास्ता अपनाया जो उसकी क्षमता में न होते हुए भी अपनाया। भविष्य में इस प्रकार के पलायन को रोकना है तो उसका एक महत्वपूर्ण समाधान महॉत्मा गॉधी के आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को अपनाकर शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के बजाय गॉवों को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में स्थापित करके किया जा सकता है।

शिक्षा व्यवस्था किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान होती है क्योंकि इसी के द्वारा नैतिकता, मूल्य एवं आदर्श एक पीढी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित होते है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा ब्रिटेन द्वारा भौतिक संसाधनों की लूट कच्चे माल के रूप में की, और उसी कच्चे माल से तैयार वस्तु को बेचने के लिए भारत के बाजार के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार भारतीय उद्योग धन्धे बन्द होते चले गये और भारतीय जनमानस बेरोजगार होता चला गया। वर्तमान समय मे विश्व के देश चीन के शहर वुहान से एक महामारी पैदा हुई। जिसने धीरे–धीरे पूरे विश्व के अपनी चपेट मे लेकर विनाश का तांण्डव किया, और यह महामारी वैश्विक महामारी में बदल गयी जिसका नाम हैं कोविड–19, (कोरोना वायरस)।[1]

इस कोरोना वायरस ने भारत को भी अपनी चपेट मे ले लिया हैं भारत सरकार को दो महीनो से ज्यादा समम तक देश में लॉक डॉउन करना पडा। लेकिन लॉक डाउन के बाद भी यह कोरोना वायरस तेजी भारत मे बढता जा रहा है, जिस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पडा है। इस वैश्विक महामारी के कारण विकट समस्याओं का सामना करना पड रहा है जैसे–लॉक डाउन के कारण सभी उत्पादन इकाईयां बन्द होने से उनमें काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गये, व फैक्ट्री मालिको ने उनका वेतन काट लिया। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के बन्द होने से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो गये। साथ ही साथ यातायात के साधन पूर्ण रूप से बन्द होने के कारण कही

आने जाने पर भी रोक लगा दी गई अर्थात जो जहां है वो वही फंसा रह गया, जिसका दंश इन मजदूरों ने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राऐ करके झेली।[2]

एक समय ऐसा था कि यह मजदूर वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की और पलायन करता था। इस कोरोना वायरस की वजह से वह भूखा, प्यासा कष्टो को झेलता हुआ अपने घर वापस तो पहुँच गया हैं लेकिन गांवो में रोजगार के अभाव में भूखमरी की कगार पर पहुँच गया है। इस बेरोजगारी की बाढ में गॉधीजी के दर्शन से हमें कुछ सीख मिलती है। गॉधीजी को बडे उद्योगो का विरोधी व लघु एवं छोटे उद्योगो का समर्थक ऐसे ही नही माना गया होगा। शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि जब भी देश में गम्भीर संकट उत्पन्न होगा तो ये बडे उद्योग जो पूजीपतियों के है वे अपने कमचारियों का साथ छोड देगे, हालांकि गॉधीजी पूजीपतियों के कभी खिलाफ नही रहे।[3]

गॉधीजी के द्वारा दिये गये लघु एवं हथकरघा उद्योगो के बारे में विचारो से स्पस्ट होता है कि वे इसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने चाहते थे। आत्मनिर्भरता की शिक्षा देश को विपरीत परिस्थितियों से सामना करने में सहायक होगी। इस कोरोना महामारी से शहरों से गांवो की और मजदूरों का पलायन होने से उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या के सामने क्या ये मजदूर रोजगार के अभाव में अपना स्वाभिमान एवं स्वावलंम्बन बचाकर अपना और अपने परिजनो का भरण पोषण कर पायेगे। भारत में लोकतंन्त्र को मजबूत बनाये रखने के लिए आत्मनिर्भरता जितनी आवश्यक है स्वावलंम्बन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि स्वावलंम्बन, आत्मनिर्भरता की पहली सीढी है।[4]

भारतीय स्वतंन्त्रता आन्दोलन के समय स्वराज एवं विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार एक प्रकार से आत्मनिर्भरता पर आधारित रहा है। प्रत्येक हाथ को काम देने में सरकारें विफल हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक आदमी अपने अनुभव पर आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकता है। गॉधीजी के विचार प्रकृति के अधिक नजदीक रहे। उन्होंने जल और जंगलों के महत्व को समझा जो व्यक्ति को ज्यादा लाभकारी थे, इसीलिए वे बडे–बडे उद्योगो के विरोधी थे। क्योंकि वे इन भौतिक संसाधनों का अंधाधुध मात्रा में प्रयोग कर प्रकृति को नंगा करने का कार्य करेंगे, और उनसे प्राप्त लाभ पूँजीपति उठायेगे। जबकि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन मनुष्य की बढती उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने भौतिक संसाधनों के असीमित प्रयोग से समाज को दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया है निर्धन वर्ग और पूँजीपति वर्ग। समाज में इस प्रकार का बढता दायरा शोषण, अत्याचार, अपराध एवं हिंसा पर आधारित होगा। अतः कहा जा सकता है कि इस वैश्विक महामारी में गॉधी के विचारों की प्रासंगिकता को समझना होगा।[5]

गॉधीजी ने शिक्षा पद्वति के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि वह रोजगार पर आधारित हो। जैसे–हैण्डीक्राफ्ट पर आधारित पाठय्क्रम। जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थाऐं पढाई के साथ–साथ ऐसे कौशलपूर्ण कार्य कराये जाये जिससे छात्रों को हुनरमंद बनाया जा सके, और उनके द्वारा बनाये गये वस्तुओं एवं सामानों को बेचकर छात्र अपना पढाई का खर्च निकाल सके। इसी के साथ–साथ शिक्षण संस्थान भी छात्र–छात्राओ द्वारा बनायी गयी वस्तुओं से आय भी प्राप्त होगी। अतः कहा जा सकता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों से दो फायदे होगे एक शिक्षण संस्थाओं की आय का स्रोत भी बना रहेगा, दूसरा छात्र भी अपनी पढाई को

लेकर परिजनों पर आश्रित नही होगे। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों अध्ययन करके छात्र जब शिक्षण संस्थाओं से पढकर निकलेगा तो वह बेरोजगारी की लाईन में नही खडा होगा। क्योंकि शिक्षण अवधि में जो कार्य एवं कौशल सीखा है उसके द्वारा वह अपने को स्वावलंबी बना सकेगा और जब वह स्वावलंबी बन जायेगा तो उसमें आत्मनिर्भर बनने का साहस उत्पन्न होगा।[6]

मनुष्य के नैतिक विकास के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि उनका मानना है कि इस भावी युवा पीढी जिसके कन्धों पर देश का वर्तमान एवं भविष्य टिका हुआ है उनका नैतिक विकास जितना उत्क्र्ष्ट श्रेणी का होगा देश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा। इस भावी पीढी को नैतिकशास्त्र की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसकी जिम्मेदारी परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं की है। क्योंकि मुख्यतया् नैतिक शिक्षा के ये तीन स्रोत ही महत्वपूर्ण माने जाते है।[7]

एक सभ्य परिवार से एक सभ्य समाज का निर्माण होता है, और एक सभ्य समाज से एक सभ्य देश एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः एक सभ्य देश बनाने के लिए देश के नागरिको का नैतिक उत्थान होना अति आवश्यक है। यदि इस भावी पीढी को नैतिकता के मार्ग पर लाना है तो सभी को चाहे वह परिवार का सदस्य हो या समाज का सभी को अपनी कथनी और करनी के अन्तर को कम करना होगा या समाप्त करना होगा। क्योंकि ये कथनी और करनी का अन्तर ही मनुष्य के चरित्र को मापने का पैमाना है। लेकिन अधिकांशत् समाज में लोगो द्वारा एक झूठ को छिपाने के लिए सैकडों झूठ बोलते है।[8]

गॉधीजी ने अपने सत्य सम्बन्धी विचारो के माध्यम से बताया है कि सत्य क्या है। सत्य वह है जो हमारी अन्तरात्मा की आवाज होती है, वही सत्य है। व्यक्ति झूठ तो बोल सकता है लेकिन उसकी अन्तरात्मा उसको सही बोलने के लिए प्रेरित भी करती है। अतः मनुष्य को कुछ भी बोलने या कार्य करने से पहले अपने अन्तहमन की बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो सत्य के करीब होती है।[9]

किसी भी देश का अतीत एवं भविष्य उस देश के युवा वर्ग पर निर्भर करता है, जो देश के निर्माण एवं विकास की आधारशिला माना जाता है। यदि इस युवा वर्ग को सही दिशा एवं दशा मिल जाये या इस युवा वर्ग को उसकी शक्ति का अहसास कर दिया जाये तो यह देश को विश्व के अग्रणी देशी की श्रेणी खडा कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में देश में बढती हुई बेरोजगारी ने इस युवा वर्ग को निराशा में डाल दिया है। ऐसे समय में इस युवा की शक्ति को जागृत करने के लिए सरकार को बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए धरातल पर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है।[10]

कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण असीमित गति से बढती हुई बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकारों को केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखकर रोजगार के जो आंकडे दिखाये जाना ओर वास्तविकता कुछ और होना, इस प्रकार का अन्तर युवा वर्ग में एक प्रकार से असन्तोष पैदा भी करता है। जिस कारण युवा वर्ग में निराशा का भाव उत्पन्न होने से राजनीति विश्वास में गिरावट का परिचय हैं। वर्तमान समय में बढती हुई बेरोजगारी के कारण कामगार वर्ग को अपनी आजीवका चलाने के लिए देश के बडे–बडे शहरों की और पलायन करते है। जिससे शहरों और गांवो का संतुलन बिगडने से शहरों पर जनसंख्या का भार बढता जाता है। क्योंकि जो शहर एक निर्धारित जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है

उससे कही ज्यादा जनसंख्या का भार वहन कर रहे है। शहरों की और प्रवासी मजदूरों का पलायन होने से शहरों की व्यवस्था भी चरमरा जाती है। जिसका प्रभाव कही न कही मनुष्य के स्वास्थ्य पर पडता है। शहरों के पास इन प्रवासी मजदूरों के लिए काम तो हो सकता है लेकिन इनके रहने के लिए उचित स्थान नही मिलता। अतः प्रवासी मजदूरो को शहर तभी तक रखने में सक्षम होते है देश में किसी प्रकार का संकट न हो।[11]

वर्तमान समय में यह सिद्व हो चुका है कि इस कोविड–19 महामारी ने कामगार मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि ये परिवार, घर–बार सभी को छोडकर शहरों की और रूख इसलिए करते है कि वहां रोजगार है। लेकिन इस महामारी ने इन प्रवासी मजदूरों को शहरों ने बेगाना बना दिया। कोराना वायरस जैसी महामारी ने इन प्रवासी मजदूरो को इतना तो सीखा ही दिया की जितनी मेहनत और कठिन परिश्रम से हम शहरो में काम करते थे यदि उसी हिम्मत और क्षमता के साथ हम गांवों में ही करेंगे तो अपनी आजीवका तो चला ही सकते है।[12]

इन प्रवासी मजदूरो का बडा वर्ग शायद ऐसा भी होगा जो किसी न किसी प्रकार का कारीगर होगा। अब उनके इस हुनर एवं कौशल से चाहे कम पैसे कमाये लेकिन गांव से शहर की और रूख शायद न करे, और अपने हुनर एवं कौशल से अपने क्षेत्र को लाभान्वित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि शहरों में जनसंख्या की भरमार होने के कारण अनेक समस्याओं ने भी जन्म लिया है, जैसे–मानवाधिकारों के हनन में वृद्वि होने से कही न कही अपराधिकरण में भी वृद्वि होती है। अतः सरकारो को इस समय इन प्रवासी मजदूरों के साथ खडा होना चाहिए। जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके, और सरकारे इन प्रवासी मजदूरों के कौशल एवं कार्यों के अनुभव से लाभ उठाकर अपने–अपने प्रदेशों को विकास एवं आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने का सकारात्मक प्रयास करना चाहिए।[13]

गॉधीजी द्वारा दिया गया ट्रस्टीशिप का सिद्वान्त को लागू करने के लिए सरकार सकारात्मक प्रयास कर सकती है। क्योंकि इस वैश्विक कोरोना महामारी में जिन लोगों ने बैकों से कर्ज स्वरूप पूँजी लोन के रूप में ले रखी है सभी उद्योगों को चाहे वे मध्यम उद्योग हो या बडे उद्योग आदि सभी को हुई हानि की भरपाई सरकार स्वंम करें। जिससे भविष्य में जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जायेगी तो उन उद्योगों से प्राप्त होने वाले लाभों से सरकार को स्वंम एवं उद्योग के स्वामी (मालिक) लाभांश को आपस में बांट ले। जिससे कोरोना वायरस के कारण उद्योग–धन्धे बंद होने से जो नुकसान मजदूर व कर्मचारी वर्ग के साथ–साथ मालिको को जो हुआ है उसकी आसानी से भरपाई की जा सकती है। इस प्रकार के कदम से वर्तमान समय में सबसे ज्यादा घाटा सरकार को उठाना पडेगा। लेकिन भविष्य में अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने पर धीरे–धीरे सरकार के इस घाटे की भरपाई आसानी से हो सकती है। साथ ही साथ देश के सभी छोटे एवं बडे उद्योग धन्धे प्राईवेट लिमिटेड हो जायेगे, जिसके ऐसा होने पर कर्मचारी वर्ग गौरवान्वित महसूस भी करेगा।[14]

इस प्रकार से प्राईवेट एवं सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी देश के प्रति ज्यादा बढ़ जायेगी और कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए काम करने हेतु सरकार को ज्यादा हाथ मिल सकेगें। क्योंकि इस कोरोना वायरस महामारी में जनजागरूकता कार्य हेतु शिक्षक समुदाय का योगदान व जरूरत के समय एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार के साथ ठीक उसी प्रकार से खडा है जैसे–सरकारी डाक्टर, पुलिस एवं अन्य सभी विभागीय

कर्मचारीगण। आदि का महत्व शायद सरकार समझे, और निजीकरण की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करने की अपेक्षा उसमें वृद्वि करें।[15]

सरकार यदि इस प्रकार की नीतियों पर कार्य नही करेगी तो भविष्य में फैक्ट्री मालिको के शोषण से कर्मचारियों को बचा पाना सम्भव नही होगा। क्योंकि इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से सीख केवल मजदूर या कर्मचारी वर्ग ने ही नही ली है, बल्कि उद्योगपतियों ने भी ली है। अतः वे भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उददे्श्य एवं नीतियों पर कार्य करेगें, ओर ज्यादा से ज्यादा लाभांश वे कर्मचारियों के शोषण के बल पर करेगा। यदि भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो भारत अपने स्वतंन्त्रा, समानता, न्याय एवं बन्धुता जैसे लोकतांन्त्रिक मूल्यों एवं आदर्शों से समझौता करने पर विवश होना पड़ सकता है। जिससे कही न कही पूँजीवाद को बढावा मिलेगा। अतः सरकार को भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने एवं लागू करनी होगी। जिस कारण कर्मचारी एवं पूँजीपति वर्ग दोनों वर्गों के बीच सामन्जस्य स्थापित किया जा सके, जिससे दोनों के अधिकार सुरक्षित भी।[16]

वर्तमान समय में सरकार एवं सरकारे ऐसे दोराहे पर खडी है कि उनके द्वारा बनायी गयी नीति यदि पूँजीपतियों के हित में होगी तो मजदूर वर्ग मे असन्तोष की भावना जाग्रत होगी, और यदि सरकार मजदूर वर्ग व उनके अधिकारों के संरक्षण में योजना बनाती है तो पूँजीपति वर्ग से सरकार को असहयोग का सामना करना पड सकता है। अतः आवश्यकता है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के भँवर में फंसी अर्थव्यवस्था रूपी नैय्या को सकुशल पार कर सके और देश को विकास के मार्ग पर ले जाये।[17]

निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि कोविड–19, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में गॉधी के विचार एक सम्पूर्ण सुझाव तो नही हो सकते है। लेकिन वर्तमान समय में उत्पन्न बेरोजगारी में उनके द्वारा दिया गया आत्मनिर्भरता का सूत्र हमें कही न कही अतीत की तरफ पीछे मुडकर देखने के लिए प्रेरित जरूर करता है। चाहे गॉधीजी का शिक्षा सम्बन्धित सिंद्वान्त हो, सत्य एवं अहिंसा का सिंद्वान्त हो, प्रकृति एवं प्रर्यावरण सम्बन्धित विचार हो, हथकरघा एवं लघु उद्योगों से सम्बन्धित विचार हो या उनका ट्रस्टीशिप का सिंद्वान्त। अतः कहा जा सकता है कि इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में उत्पन्न बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याओं के समाधान में उनके विचार प्रासंगिक अवश्य है। अतः गॉधीजी के विचारों की महत्ता को अनदेखा नही किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूचीः–

(1) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद– चम्पारण में महात्मा गॉधी, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2007, पृ–38

(2) डॉ0 कृष्णा द्विवेदी– बिहार की हिन्दी पत्रकारिता, प्रवाल प्रकाशन, पटना, 1996, पृ0–56

(3) गोपीनाथ धवन– दि पालिटिकल फलासफी ऑफ महात्मा गॉधी, नवजीवन प्र0 म0, 1957 पृ0–95

(4) कि0घ0 मशरूवाला– गॉधी और समाजवाद, अहमदाबाद, पैन इन इण्डिया, 1956, पृ0–214

(5) चन्द्रराज भण्डारी– गॉधी दर्शन, इन्दौर, गॉधी हिन्दी मन्दिर, 1959, पृ0–68

(6) डी0एम0 दत्ता– दि फलासफी ऑफ महात्मा गॉधी, मैडिसन यूनिवर्सिटी ऑफ विश्कोनसिया प्रेस, 1953, पृ0–149
(7) यू0एन0 ढेबर– गॉधी ए पॉलिटिकल आइडियोलिस्ट, भारतीय विद्या भवन, बम्बई , 1964,पृ0–63
(8) एलेक जैण्डर ग्रास– सोशल एण्ड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गॉधी, आई0सी0डब्लू0ए0, नई दिल्ली, 1949, पृ0–86
(9) एस0एन0 अग्रवाल– गॉधीवादी योजना के सिंद्वान्त, आगरा, 1944, पृ0–72
(10) कालेलकर– गॉधी के व्यक्तिगत विचार, स0सा0 मण्डल, इलाहाबाद, 1939, पृ0–38
(11) रामशकल पाण्डेय– शिक्षा की दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, 10 जी0 संस्करण, 2011, पृ0–122
(12) मोहनदास कर्मचन्द गॉधी– सत्य के प्रयोग आत्मकथा, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1996, पृ0–96
(13) मोहनदास कर्मचन्द गॉधी– बुनियादी शिक्षा, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद,1970, पृ0–54
(14) मोहनदास कर्मचन्द गॉधी– मेरे सपनो का भारत, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद, 1969, पृ0–87
(15) पुखराज जैन– प्रमुख राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1987, पृ0– 81
(16) मोहनदास कर्मचन्द गॉधी– 'बुनियादी शिक्षा' नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद, 1970, पृ0–131
(17) तदैव, पृ0–134

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH